(160)

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्याः 257/XVII-3/12-07(65)/2007

प्रेषक,

बी0आर0 टम्टा
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 26 मार्च, 2012

विषयः **चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) की मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8/18/2011–पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 23 फरवरी, 2012 **(छायाप्रति संलग्न)** के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में उक्त योजनान्तर्गत धनराशि रू0 6,08,952/-- (रू0 छः लाख आठ हजार नौ सौ बावन मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। अवचनद्व मदों में से व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय। योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) उक्त आवंटित धनराशि किसी मद पर व्यय करने से पूर्व जिसमें वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

(iii) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से **अनुदान संख्या–15** "आयोजनागत्" शब्द स्पष्ट किया जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

(iv) वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

(v) मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मितव्ययिता/अबचनवद्व की मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति कराना सुनिश्चित करें।

(vi) यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(VII) अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(VII) उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

(IX) बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्यय की अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष में **लेखाशीर्षक–2250- अन्य सामाजिक सेवाएं–800–अन्य व्यय–01–के0आ0 / के0पु0यो0–0102–अल्पसंख्यक छात्रों के के लिए उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र सहायतित) के मानक मद 21–छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या– 432(P)/XXVII(3)/2011-12 दिनांक 23 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(बी0आर0 टम्टा)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 257 (1) / XVII-3/12-07(65)/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, नैनीताल / देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
12. अवर सचिव, अल्पंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्याः 6/4/2011 –12पी0पी0 (पी0पी0आर0) दिनांक 23 फरवरी, 2012 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
13. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून। 14. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(बी0आर0 टम्टा)
अपर सचिव।